10 लाख का ट्रांजेक्शन करना हुआ आसान

1 अप्रैल 2026 से बदलेंगे पैन नियम

कैश, होटल बिल, वाहन, इंश्योरेंस, क्रिप्टो पर राहत

नई दिल्ली,10 फरवरी. इनकम टैक्स सिस्टम को सरल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने पैन कार्ड से जुड़े कई नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा है. 'नए इनकम टैक्स एक्ट, 2025' के ड्राफ्ट नियमों में छोटे ट्रांजेक्शन पर कागजी औपचारिकताएं कम करने और बड़े लेनदेन पर निगरानी मजबूत करने की कोशिश दिखती है.

प्रस्तावों के मुताबिक अब साल भर में 10 लाख तक के कैश ट्रांजेक्शन पर पैन की अनिवार्यता नहीं होगी. होटल बिल, इवेंट पेमेंट और कुछ वाहनों की खरीद में भी पैन लिमिट बढ़ाई जा रही है.

होटल बिल भुगतान की पैन सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख करने का प्रस्ताव है. यही सीमा कन्वेंशन सेंटर और इवेंट मैनेजमेंट पेमेंट पर भी लागू होगी. प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री या गिफ्ट के मामलों में पैन अनिवार्यता की सीमा रु .10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख करने का सुझाव है. वाहन खरीद में भी बड़ा बदलाव प्रस्तावित है. 5 लाख से महंगी मोटरसाइकिल या किसी भी मोटर व्हीकल की खरीद पर पैन देना होगा. मौजूदा नियमों में दोपहिया के लिए पैन शर्त नहीं थी, जबकि चार पहिया के लिए हर कीमत पर अनिवार्य था. इंश्योरेंस कंपनियों के साथ 'अकाउंट-बेस्ड रिलेशनशिप' शुरू करने पर पैन जरूरी होगा, जिससे ग्राहक का स्थायी प्रोफाइल बनेगा.

दूसरी ओर, इंश्योरेंस कंपनियों के साथ 'अकाउंट-बेस्ड रिलेशनशिप' और क्रिप्टो ट्रांजेक्शन पर जानकारी साझा करने जैसे प्रावधानों से पारदर्शिता बढ़ेगी. सीबीडीटी ने इन नियमों पर सुझाव मांगे हैं और इन्हें 1 अप्रैल 2026 से लागू करने की तैयारी है. बदलावों का मकसद आम लोगों, छोटे व्यापारियों और सेवा क्षेत्र को राहत देना है, जबकि बड़े और संदिग्ध लेनदेन पर सख्ती बनाए रखना है.

ड्राफ्ट नियमों के अनुसार, बैंक या को-ऑपरेटिव बैंक में अब एक वित्त वर्ष में रु.10 लाख या उससे अधिक कैश जमा/निकासी पर ही पैन देना अनिवार्य होगा. अभी यह सीमा एक दिन में 50,000 से ज्यादा कैश जमा पर लागू होती है. इससे छोटे व्यापारियों और दैनिक नकद लेनदेन करने वालों को बड़ी राहत मिल सकती है.

रुपया एक पैसे कमजोर

मुंबई, 10 फरवरी. अंतर बैंकिंग मुद्रा बाजार में रुपया सोमवार को एक पैसे कमजोर हुआ और कारोबार की समाप्ति पर एक डॉलर 90.66 रुपये का बोला गया. भारतीय मुद्रा लगातार दूसरे दिन कमजोर हुई है. पिछले कारोबारी दिवस पर यह 31 पैसे टूटकर 90.65 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुई थी. रुपये में आज काफी उतार-चढ़ाव देखा गया. यह एक पैसे फिसल कर 90.66 रुपये प्रति डॉलर पर खुला और बीच कारोबार में ऊपर 90.37 रुपये तथा नीचे 90.77 रुपये प्रति डॉलर तक गया. वाणिज्यिक बैंकों की ओर से डॉलर की खरीद बढ़ाने से रुपये पर दबाव रहा. हालांकि अन्य सभी कारकों ने इसे समर्थन दिया. दुनिया की अन्य प्रमुख मुद्राओं के बास्केट में डॉलर सूचकांक में 0.6 प्रतिशत की भारी गिरावट से रुपये को बल मिला. अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में नरमी से भी रुपये की गिरावट सीमित रही.

तेजी के बाद टूटे सोना-चांदी के रेट

चांदी 5,800 रु . फिसली, सोना 1,300 रु . सस्ता

नई दिल्ली, 10 फरवरी. दो कारोबारी सत्रों की तेज बढ़त के बाद मंगलवार को सर्राफा बाजार में मुनाफावसूली हावी दिखी. सोने और चांदी की कीमतों में तेज गिरावट दर्ज की गई, जिससे बाजार की हालिया गर्मी ठंडी पड़ती नजर आई.

दोपहर तक सोना करीब रु. 1,300 सस्ता होकर 1.57 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर आ गया, जबकि चांदी रु. 5,800 टूटकर 2.61 लाख रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई. विशेषज्ञों के अनुसार, अमेरिकी डॉलर में मजबूती और इस सप्ताह आने वाले अमेरिकी रोजगार व महंगाई आंकड़ों की प्रतीक्षा ने कीमती धातुओं पर दबाव बनाया है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोना-चांदी में गिरावट का असर घरेलू बाजार पर साफ दिखा. इससे पहले सोमवार को चांदी 2.72 लाख और सोना 1.58 लाख के स्तर तक पहुंच गए थे. तेजी के बाद आई यह गिरावट बाजार की अस्थिरता को दर्शाती है. मंगलवार को शुरुआती कारोबार में सोना रु.960 सस्ता होकर 1.57 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया. वहीं चांदी रु. 2,640 गिरकर 2.61 लाख रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई. दोपहर तक गिरावट और गहरी हो गई, जहां सोने में कुल रु.1,300 और चांदी में रु.5,800 तक की कमजोरी दर्ज की गई. अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी दबाव दिखा.

स्पॉट सिल्वर 2.5% गिरकर 81.31 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई. डॉलर इंडेक्स में मजबूती और निवेशकों की सतर्कता इसका प्रमुख कारण रही. घरेलू वायदा बाजार एमसीएक्स में सोमवार को जोरदार तेजी दर्ज की गई थी. एमसीएक्स गोल्ड अप्रैल फ्यूचर्स रु . 2,943 चढ़कर 1,58,394 रुपए पर बंद हुआ था, जबकि एमसीएक्स सिल्वर मार्च फ्यूचर्स रु . 12,853 की बढ़त के साथ 2,62,745 रुपए पर बंद हुआ.

विशिष्ट इस्पात के लिए पीएलआई शुरू

नई दिल्ली,10 फरवरी. सरकार ने आयात पर निर्भरता कम करने के लिए विशिष्ट श्रेणी के इस्पात के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना 1.2 की सोमवार को शुरुआत की. योजना का उद्देश्य उच्च मूल्य वाले उन विशिष्ट श्रेणी के इस्पात के घरेलू निर्माण को प्रोत्साहित करना है जिनके लिए इस समय हम पूरी तरह से आयात पर निर्भर हैं.

इस्पात एवं भारी उद्यम मंत्री एच.डी. कुमारस्वामि की मौजूदगी में यहां विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में योजना की शुरुआत की गयी. इस मौके पर कई कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर भी किये गये. श्री कुमारस्वामि ने कहा कि देश में विशिष्ट श्रेणी के इस्पात के निर्माण के लिए मजबूत और वैश्विक प्रतिस्पर्धी पारितंत्र तैयार करने की दिशा में पीएलआई 1.2 एक महत्वपूर्ण कदम है. यह योजना आधुनिक और रणनीतिक इस्पात उत्पादों के लिए घरेलू क्षमता निर्माण को बढ़ावा देकर मेक-इन-इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को बढ़ावा देती है. मंत्रालय ने बताया कि पीएलआई 1.2 के तहत आज 55 कंपनियों के साथ 85 एमओयू पर हस्ताक्षर किये गये. कंपनियों ने 11,887 करोड़ रुपये के निवेश की प्रतिबद्धता जतायी. इन परियोजनाओं से वित्त वर्ष 2030-31 तक विशिष्ट श्रेणी के 87 लाख टन इस्पात निर्माण की क्षमता विकसित होने की उम्मीद है.

बिजली की मांग जनवरी में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची

मुंबई, 10 फरवरी. उत्तरी और पूर्वी हिस्से में शीतलहर के कारण देश में बिजली की मांग जनवरी में 4.5 प्रतिशत बढ़कर करीब 143 अरब यूनिट पर पहुंच गयी जो कम से कम 2010 के बाद का रिकॉर्ड है. बाजार अध्ययन एवं साख निर्धारक एजेंसी क्रिसिल रेटिंग्स की मंगलवार को जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि जनवरी के पूर्वार्ध में उत्तरी और पूर्वी भारत में भयंकर शीतलहर रही जिससे घरों को गर्म रखने के लिए बिजली की मांग में वृद्धि देखी गयी. पिछले साल जनवरी में बिजली की मांग 136 अरब यूनिट रही थी. क्रिसिल रेटिंग्स के अनुसार 08 जनवरी से 14 जनवरी के बीच पश्चिमी और पश्चिमोत्तर भारत में औसत न्यूनतम तापमान दो से चार डिग्री सेल्सियस के बीच रहा. उत्तर भारत में बिजली की मांग 5.5 प्रतिशत अधिक रही. रिपोर्ट में कहा गया है कि इसमें औद्योगिक मांग का भी योगदान रहा.

वाहनों की खुदरा बिक्री 17 .6 प्रतिशत बढ़ी

नई दिल्ली, 10 फरवरी. वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) सुधारों और अच्छी फसल के कारण वाहनों की खुदरा बिक्री जनवरी में सालाना आधार पर 17.61 प्रतिशत बढ़कर 27,22,558 इकाई पर पहुंच गयी.

वाहन डीलरों के महासंघ (फाडा) द्वारा मंगलवार को जारी आंकड़ों में बताया गया है कि जनवरी में दुपहिया की बिक्री एक साल पहले के मुकाबले 20.82 फीसदी बढ़कर 18,52,870 इकाई पर पहुंच गयी. इस दौरान यात्री वाहनों की बिक्री 5,13,475 इकाई रही जो 7.22 प्रतिशत की वृद्धि दिखाता है. वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री 15.07 प्रतिशत और तिपहिया की 18.80 प्रतिशत बढ़ी. देश में जनवरी में कुल 1,07,486 वाणिज्यिक वाहन और 1,27,134 तिपहिया वाहन बिके. ट्रैक्टरों की बिक्री 22.89 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 1,14,759 इकाई पर पहुंच गयी. निर्माण उपकरणों की बिक्री में 21.09 प्रतिशत की गिरावट रही और यह 6,834 इकाई दर्ज की गयी. बिक्री बढ़ाने में सबसे अधिक योगदान दुपहिया वाहनों का रहा. दुपहिया वाहनों की 56 प्रतिशत बिक्री ग्रामीण क्षेत्रों में और 44 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में हुई. यात्री वाहनों (कार, उपयोगी वाहन और वैन) की में 59.2 प्रतिशत बिक्री शहरी और 40.8 प्रतिशत ग्रामीण इलाकों में हुई.

फाडा के अध्यक्ष सी.एस. विग्नेश्वर ने कहा कि इस वृद्धि में जीएसटी सुधारों के बाद जारी तेजी, अच्छी फसल के बाद ग्रामीण इलाकों में पर्याप्त आय और यात्री परिवहन तथा माल ढुलाई की मांग का सबसे अधिक योगदान रहा. उन्होंने बताया कि निर्माण उपकरणों की जनवरी 2025 में बहुत अच्छी बिक्री हुई थी और इसलिए तुलनात्मक रूप से इस साल जनवरी में उसके आंकड़े गिरावट में हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि 72.56 प्रतिशत डीलरों का मानना है कि फरवरी में भी बिक्री में तेजी जारी रहेगी.

चावल, चीनी, खाद्य तेलों के दाम बढ़े, दालों में घट-बढ़

नई दिल्ली, 10 फरवरी. घरेलू थोक जिंस बाजारों में मंगलवार को चावल के औसत भाव बढ़ गये. चावल के साथ चीनी और खाद्य तेलों की कीमतों में भी तेजी रही जबकि गेहूं के भाव गत दिवस के स्तर पर पड़े रहे. दालों की कीमतों में उतार-चढ़ाव रहा. औसत दर्जे के चावल की औसत कीमत दो रुपये बढ़कर 3,852 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुंच गयी. गेहूं 2,849 रुपये प्रति क्विंटल पर लगभग स्थिर रहा. आटा चार रुपये महंगा हुआ. दाल-दलहनों में मिलाजुला रुख रहा. चना दाल औसतन 15 रुपये प्रति क्विंटल सस्ती हुई. तुअर दाल की औसत कीमत 42 रुपये और उड़द दाल की 20 रुपये बढ़ गयी. मसूर दाल 12 रुपये और मूंग दाल सात रुपये प्रति क्विंटल महंगी हुई.

ब्रोकिंग कंपनियां नीतियों में बदलावों से बचने अपनाएं विविधीकरण : क्रिसिल

मुंबई, 10 फरवरी. बाजार अध्ययन एवं साख निर्धारक एजेंसी क्रिसिल रेटिंग्स ने सरकारी नीतियों में बदलाव से बचने के लिए ब्रोकिंग कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो में विविधिकरण की सलाह दी है.

एजेंसी की मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट में डेरिवेटिव्स पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स में वृद्धि की गयी है. इससे ब्रोकिंग कंपनियों को चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा. इससे पहले, पिछली कुछ तिमाहियों में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने कुछ नियामक बदलाव भी किये थे जिनका उद्देश्य अनुमान आधारित गतिविधियों में कमी लाना, खुदरा निवेशकों के हितों की रक्षा और बाजार में पारदर्शिता को बढ़ावा देना है. क्रिसिल रेटिंग्स की निदेशक मालविका भोटिका ने 25 ब्रोकिंग कंपनियों के प्रदर्शन के विश्लेषण के आधार पर कहा कि जिन कंपनियों ने अपने राजस्व के स्रोतों में विविधता रखी है, वे इन उतार-चढावों से ज्यादा अच्छे से निपटने में सक्षम रहे.

जी 20 देशों में भारत की सबसे तेज ग्रोथ

वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर एक सकारात्मक तस्वीर

नई दिल्ली, 10 फरवरी. वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर एक सकारात्मक तस्वीर सामने आई है. ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने अनुमान जताया है कि वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की जीडीपी 6.4प्रतिशत की दर से बढ़ेगी. यह रफ्तार जी 20 देशों में सबसे तेज मानी जा रही है.

एजेंसी ने मजबूत घरेलू खपत, सरकार के नीतिगत फैसलों, स्थिर बैंकिंग सिस्टम और टैक्स सुधारों को इस अनुमान की मुख्य वजह बताया है. हालांकि यह अनुमान सरकार के इकोनॉमिक सर्वे और आरबीआई के आकलन से थोड़ा कम है, फिर भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की आर्थिक स्थिति को लेकर भरोसा दर्शाता है. रिपोर्ट के मुताबिक जीएसटी नियमों में बदलाव, पर्सनल इनकम टैक्स में राहत और भारत-अमेरिका ट्रेड डील से बाजार में मांग और निवेश बढ़ेगा.

साथ ही, महंगाई नियंत्रण में रहने से आरबीआई आगे भी ब्याज दरों में कटौती कर सकता है, जिससे कर्ज सस्ता होगा और खपत को बल मिलेगा. मूडीज की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार वित्त वर्ष 2027 में 6.4प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो जी20 समूह में सबसे अधिक है. एजेंसी का कहना है कि भारत में घरेलू मांग लगातार मजबूत बनी हुई है और सरकारी नीतियां खपत को बढ़ावा दे रही हैं.

शेयर बाजारों में लगातार बढ़त

मुंबई, 10 फरवरी. घरेलू शेयर बाजारों में मंगलवार को लगातार तीसरे दिन तेजी रही और बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 200 अंक से अधिक के बढ़त के साथ बंद हुआ.

सेंसेक्स 208.17 अंक (0.25 प्रतिशत) चढ़कर 84,273.92 अंक पर पहुंच गया. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 सूचकांक 67.85 अंक यानी 0.26 प्रतिशत ऊपर 25,935.15 अंक पर रहा. यह दोनों का 07 जनवरी के बाद का उच्चतम स्तर है. चौतरफा लिवाली के बीच निफ्टी मिडकैप-50 सूचकांक 0.32 प्रतिशत और निफ्टी स्मॉलकैप-100 सूचकांक 0.49 प्रतिशत चढ़ गया. ऑटो, मीडिया, धातु, रियलटी और तेल एवं गैस सेक्टरों में लिवाली का जोर रहा जबकि फार्मा, स्वास्थ्य, रसायन और सार्वजनिक बैंकों के समूहों में बिकवाली हावी रही. सेंसेक्स की कंपनियों में इटरनल का शेयर पांच प्रतिशत से अधिक चढ़ा.

सेंसेक्स 208 .17 अंक चढ़कर 84,273 .92 अंक पर पहुंच गया

निफ्टी-50 सूचकांक 67 .85 अंक यानी 0 .26 प्रतिशत ऊपर 25,935 .15 अंक

समाचार विशेष

क्या भाजपा में जाएंगे नवजोत सिद्धू?

पूर्व मंत्री ने अटकलों पर लगा दिया विराम, पत्नी ने छोड़ी थी पार्टी

जालंधर. पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू की भाजपा में संभावित वापसी की चर्चाओं ने पंजाब की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है. इन अटकलों के बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मनोरंजन कालिया ने एलान करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि सिद्धू के लिए पार्टी के दरवाजे बंद हैं.

मनोरंजन कालिया ने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू पहले भाजपा छोड़कर कांग्रेस में गए और वहां रहते हुए पार्टी व नेतृत्व पर लगातार हमले किए. अब राजनीतिक परिस्थितियां बदलने पर उनकी वापसी की बातें सामने आ रही हैं, लेकिन भाजपा अवसरवाद की राजनीति को स्वीकार नहीं करती. उन्होंने कहा कि पार्टी की एक स्पष्ट विचारधारा और अनुशासन है, जिससे कोई समझौता नहीं किया जा सकता.

उधर, नवजोत सिंह सिद्धू की ओर से भाजपा में वापसी को लेकर अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है. हालांकि कांग्रेस से उनकी बढ़ती दूरी और लंबे समय से राजनीतिक सक्रियता से दूर रहने के कारण अटकलों को बल मिला है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ऐसे राजनीतिक संकेत और बयानबाजी और तेज हो सकती है. बता दें कि कुछ दिन पहले नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर इसका एलान किया था. उन्होंने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग पर पार्टी को नुकसान पहुंचाने का आरोप भी लगाया.

कांग्रेस ने नवजोत कौर को किया था निलंबित

उल्लेखनीय है कि नवजोत कौर को पिछले महीने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित किया गया था. उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए 500 करोड़ रुपये देने के आरोप लगाकर राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया था. नवजोत कौर ने आरोप लगाया कि वड़िंग आप के साथ समझौता कर पार्टी को निजी लाभ के लिए बेच रहे हैं. उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ सस्पेंशन लेटर तैयार था लेकिन 12 वरिष्ठ नेताओं ने मिलकर मुझे नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया और उन्हें बड़े पदों पर नियुक्त कर दिया गया.

मजीठिया बाहर आए, चुनाव की तैयारी

चंडीगढ़. अकाली दल के बड़े नेता और पार्टी प्रमुख सुखबीर सिंह बादल की पत्नी हरसिमरत कौर बादल के भाई बिक्रम मजीठिया जेल से छूट गए हैं. राज्य की आम आदमी पार्टी की सरकार ने उनको रोकने का बड़ा प्रयास किया.

ध्यान रहे राज्य के विजिलेंस विभाग ने उनके खिलाफ कई आरोप लगाए हैं. भ्रष्टाचार के साथ साथ नशीले पदार्थों की तस्करी आदि से जुड़े मुकदमे भी हैं. इसलिए उनको काफी समय तक जेल में रहना पड़ा. फिर जब उनको जमानत मिल गई तो पंजाब सरकार ने अदालत से गुहार लगाई कि मजीठिया को पंजाब में नहीं रहने दिया जाए और उनको सोशल मीडिया के इस्तेमाल से रोका जाए. अदालत ने दोनों मांग ठुकरा दी.

सो, अब मजीठिया पंजाब में रहेंगे और सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल करेंगे. अकाली दल ने अदालत के फैसले का स्वागत किया है और मजीठिया की रिहाई को जश्न का बड़ा मौका बनाया है. ध्यान रहे पंजाब चुनाव में अब एक साल का समय रह गया है. बादल परिवार और मजीठिया परिवार जट्ट सिख वोट में अपना आधार मजबूत करने में लगा है.

क्या है लक्ष्मी भंडार योजना?

वो स्कीम जिसके दम पर भाजपा को मात दे देती हैं ममता!

कोलकाता. प. बंगाल विधानसभा चुनाव में अब बस कुछ महीने बचे हैं. गुरुदेव रवींद्रनाथ नाथ टैगोर द्वारा लिखे प्रसिद्ध बंगाली गीत तोबे एकला चलो रे वहां की राजनीति के लिए बिल्कुल सटीक बैठ रही है. एक तरफ जहां बंगाल में बीजेपी अकेले दम पर मैदान में उतर रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी इंडी गठबंधन का वहां कोई नाम-ओ-निशान नहीं है.

मतलब साफ है कि ममता दीदी अकेले बीजेपी से लोहा लेने के लिए तैयार हैं. वहीं, बिहार में मिली करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस के भीतर बंगाल चुनाव को लेकर कोई खास उत्साह नजर नहीं आ रहा. कुल मिलाकर बंगाल चुनाव में मुकाबला बीजेपी बनाम तृणमूल कांग्रेस है.

घुसपैठ को मुद्दा बनाकर बीजेपी ने बंगाल चुनाव का शंखनाद कर दिया है. बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी घुसपैठ हितैषी है. वोट बैंक बचाने के लिए ममता दीदी, देश को खतरे में डाल रही हैं. वहीं दूसरी ओर, ममता दीदी ने विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर (स्क्रूक) की खामियों को उजागर करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गईं. घुसपैठिए और एसआईआर जैसे मुद्दों ने भले ही बंगाल में राजनीतिक सरगर्मी तेज कर दी हो, लेकिन चुनाव सिर्फ नैरेटिव या एजेंडे पर नहीं लड़ा जाता.

1000 नहीं, हम 3000 रुपये देंगे: बीजेपी- ममता दीदी के इन लोक लुभावन वादों को बीजेपी के नेता भी ध्यान से सुनते रहे. मुख्यमंत्री ममता दीदी के वादों को सुनने के तुरंत बाद बीजेपी नेता और बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो लक्ष्मी भंडार के तहत 3000 रुपये दिए जाएंगे. यानी टीएमसी ने लाभार्थियों को 1000 रुपये देने का वादा किया है, तो बीजेपी ने 3000 रुपये देने की बात कही है.

ममता का ब्रह्मास्त्र

कुछ महीने पहले ही बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुआई में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को प्रचंड जीत मिली. इस जीत का सबसे बड़ा एक्स-फैक्टर न तो एसआईआर था, न ही बेरोजगारी जैसे मुद्दे. वोट तो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना जैसी लोक कल्याणकारी योजनाओं और सरकारी स्कीम पर ही पड़े. यह बात ममता दीदी भी बेहतर ढंग से समझ चुकी हैं. इसी इसीलिए उन्होंने अपना ब्रह्मास्त्र यानी लक्ष्मी भंडार योजना को और सशक्त करने का मन बना लिया. साल 2021 विधानसभा चुनाव और साल 2024 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी के शानदार प्रदर्शन के पीछे इस स्कीम का बड़ा हाथ है.

विशेष | **क्या 2027 में फिर काम आएगा 2007 वाला ब्राह्मण फॉर्मूला?**

मायावती की सोशल इंजीनियरिंग 2 .0

लखनऊ. उत्तर प्रदेश की सियासत में अपनी खोई हुई जमीन तलाश रहीं बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती एक बार फिर अपने पुराने और सफल सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले की ओर लौटती दिख रही हैं. हाल में फिल्म घूसखोर पंडत के नाम को लेकर उपजे विवाद में जिस तरह मायावती ब्राह्मण समाज के समर्थन में उतरीं, उसने राजनीतिक विश्लेषकों को चौंका दिया है. सवाल उठ रहा कि क्या मायावती 2007 के उस करिश्मे को 2027 में दोहरा पाएंगी, जिसने उन्हें पूर्ण बहुमत की सत्ता दिलाई थी?

मायावती का राजनीतिक सफर दलितों के हक की लड़ाई से शुरू हुआ, लेकिन 2007 में उन्होंने एक ऐतिहासिक प्रयोग किया. उन्होंने दलित-मुस्लिम समीकरण में ब्राह्मणों को जोड़कर इसे सोशल इंजीनियरिंग का नाम दिया. उस दौर में बीएसपी के नारे बदल गए थे-हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा-विष्णु-महेश है.

इन नारों ने सवर्णों को पार्टी के करीब लाया. नतीजा यह हुआ कि 86 ब्राह्मण उम्मीदवारों में से 41 चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे और मायावती ने अपनी सरकार में 7 ब्राह्मणों को कैबिनेट मंत्री बनाकर उन्हें बड़ा सम्मान दिया.

19 साल बाद बदली सियासी हकीकत- जानकारों का मानना है कि 2007 और 2026 की परिस्थितियों में जमीन-आसमान का अंतर है. 19 साल पहले जब ब्राह्मण मायावती के साथ गए थे, तब उत्तर प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस दोनों बेहद कमजोर स्थिति में थीं और मुलायम सिंह यादव की सरकार के खिलाफ भारी गुस्सा था. आज भाजपा एक मजबूत शक्ति है और यूपी का बड़ा सवर्ण वोट बैंक उसके साथ मजबूती से खड़ा है.

पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह का कहना है कि ब्राह्मण सनातनी है और सनातन का मतलब भाजपा है. ऐसे में मायावती की कोशिशें शायद ही रंग लाएं.

वजूद बचाने की जद्दोजहद

वर्तमान में बसपा की हालत काफी नाजुक है. लोकसभा में पार्टी का एक भी सांसद नहीं है और विधानसभा में केवल एक विधायक बचा है. यहां तक कि मायावती का अपना कोर दलित वोट बैंक भी धीरे-धीरे अन्य पार्टियों की ओर खिसक रहा है. ऐसे में अपने जन्मदिन पर ब्राह्मणों को सम्मान देने का वादा करना और फिल्म विवाद पर स्टैंड लेना, उनके डूबते राजनीतिक जहाज को सहारा देने की एक कोशिश मात्र नजर आ रहा है. पूर्व सीएम मायावती के लिए चुनौती सिर्फ ब्राह्मणों को जोड़ना नहीं, बल्कि अपने पुराने समर्थकों के बीच फिर से विश्वास जगाना भी है.